यूनियन कैबिनेट ने भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम को दी मंजूरी

मेरठ मेट्रो को भी मिली मंजूरी

नई दिल्ली, फरवरी 19: यूनियन कैबिनेट ने आज दिल्ली-ग़ज़िआबाद-मेरठ के बीच भारत की पहली रीजनल रेल तथा मेरठ मेट्रो को मंजूरी दे दी हैं। हाई स्पीड, हाई-फ़्रीक्वेंसी, सुरक्षित, विश्वसनीय, आरामदायक और स्वच्छ रेल आधारित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प्रदान करने के साथ आरआरटीएस ट्रैन 82 किमी लंबे स्ट्रेच को 60 मिनट से कम समय में करेगी।

एक शहर के केंद्र से, दूसरे शहर के केंद्र को जोड़ते हुये, आरआरटीएस ट्रेन प्रदूषण को कम करेगी और एक लाख से अधिक निजी वाहनो को सड़को से कम करेगी | हाइ स्पीड मोबिलिटी आर्थिक गतिविधियों के साथ संतुलित सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देगी और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार भी लाएगी।

मेरठ में 18 km पर 12 स्टेशन्स के साथ मेट्रो सेवाएँ, जिसका संचालन भी आरआरटीएस के बुनियादी ढांचे पर होगा, जो कुशल क्षेत्रीय संपर्क प्रदान करने के अलावा मेरठ के नागरिकों के स्थानीय आगवमन की जरूरतों को पूरा भी पूरा करेगी |
आरआरटीएस ट्रेन आधुनिक सुविधाओं सीसीटीवी सर्विलेंस सिक्योरिटी, मोबाइल/लैपटाप चार्जिंग पॉइंट्स, एयरप्लेन की तरह बैठने और सामान रखने की सुविधा इत्यादि से सुसज्जित होगी | प्रत्येक ट्रेन में एक बिजनेस कोच और महिलाओं के लिए अलग कोच की भी सुविधा होगी अथवाविशेष रूप से विकलांगो के लिए यूनिवर्सल एक्सेसीबिलिटी होगी | यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने के लिए आरआरटीएस स्टेशनों को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन्स, मेट्रो स्टेशन्स, आईएसबीटी और अन्य कई परिवहन साधनो से जोड़ा जाएगा |

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर पहला कॉरीडोर होगा जिसको पहले चरण के प्राथमिकता वाले तीनों कॉरीडोर में लागू करने की योजना है | अन्य दो कॉरीडोर दिल्ली-गुरुग्राम-अलवर तथा दिल्ली- पानीपत है | आरआरटीएस प्रायोरिटी कॉरिडोर इंटरापरबल होंगे, जिससे यात्रियों को एक से दूसरे कॉरिडोर में यात्रा करने के लिए ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी |

जियो-टेक्निकल इन्वैस्टिगेशन, पाइल लोड टेस्टिंग, सड़क चौड़ीकरण कार्य और डिटेल्ड इंजीनियरिंग जैसे पूर्व-निर्माण गतिविधियां पहले से ही अग्रिम चरण में हैं। इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी एनसीआरटीसी है जो इसके निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए तैयार है | सिविल निर्माण के लिए पहले से ही टेंडर जारी किया जा चुके है |
परियोजना की कूल लागत: 30,274 करोड़ है|

एनसीआर में आरआरटीएस परियोजनाओं को डिजाइन, निर्माण, वित्तीय, संचालन और रखरखाव के लिए एनसीआरटीसी अधिकृत है और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करता है।